



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2017/माघ 19, 1938

No. 334]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2017/MAGHA 19, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

का.आ. 369(अ).—जबकि, सेवाओं अथवा लाभों अथवा राजसहायताओं की आपूर्ति के लिए पहचान कागजात के रूप में आधार के उपयोग से सरकार की आपूर्ति प्रक्रिया सरल होती है। इससे पारदर्शिता और दक्षता आती है और सरल एवं निरंतर रीति से लाभार्थियों को उनके अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं और आधार पहचान साबित करने के लिए अनेक कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निराकरण करता है।

और जबकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) फसल क्षति के विपरीत व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है इसलिए किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है और किसानों को सभी खरीफ खाद्यान्नों और तिलहन फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी खाद्यान्नों और तिलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक अथवा बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अधिकतम प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

और जबकि, वास्तविक प्रीमियम और किसानों द्वारा भुगतान योग्य बीमा शुल्क की दर के बीच अंतर को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। केन्द्र सरकार के शेयर में भारत की समेकित निधि से किया गया व्यय शामिल होता है।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य राजसहायताओं, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016, (2016 का 18) (इसके पश्चात् कथित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्र सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

1. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की किसी भी फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए आधार प्रमाणीकरण अथवा आधार होने का सबूत प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
2. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की किसी भी फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने वाला कोई भी किसान जो आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं है, एतद्वारा आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है तथा यदि वह कथित अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है तो ऐसे व्यक्ति किसी आधार नामांकन केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं (आधार के लिए नामांकन कराने के लिए सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।
3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के कृषि अथवा बागवानी अथवा सहकारिता विभागों से लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाओं का प्रबंध अथवा ऑफर करना अपेक्षित होता है जो आधार के लिए अभी नामांकित नहीं हुए हैं और ब्लाक अथवा तहसील अथवा तालुके में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न होने के मामले में संबंधित कृषि अथवा बागवानी अथवा सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान यूआईडीएआई के पंजीयक के साथ समन्वय करके सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान की जाएं अथवा आने वाले यूआईडीएआई पंजीयक द्वारा आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान की जाएं।

प्रदान किया गया कि व्यक्ति को आधार मिलने तक कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की किसी भी फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा किसानों द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात् :-

- i. फोटो के साथ बैंक पासबुक; और
- ii. आधार नामांकन आई डी पर्ची, यदि वह नामांकित है; अथवा
- iii. उसका मतदाता पहचान पत्र; अथवा
- iv. किसान फोटो पासबुक; अथवा
- v. नरेगा जॉब कार्ड; अथवा
- vi. पैरा 2 के उप पैरा (2) में निर्दिष्टानुसार आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति के साथ ड्राइविंग लाइसेंस।
- vii. संलग्न प्रपत्र में घोषणापत्र कि उसने किसी अन्य बैंक खाते के तहत समान खसरा नम्बर/संख्या में उसी फसल के लिए फसल बीमा प्राप्त नहीं किया है।

आगे प्रदान किया गया कि इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त कागजात की जांच की जाएगी।

2. फसल बीमा पाने वाले किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए, कृषि अथवा बागवानी अथवा सहकारिता विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि मित्र के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं, सहकारी समितियों की सभी शाखाएं, ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएं और इससे जुड़े अन्य कार्यालयों को निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित प्रबंध करते हैं, अर्थात् :-

(1) फसल बीमा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में आवेदकों अथवा किसानों को जागरूक बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं, सहकारी समितियों की सभी शाखाओं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं, कृषि अथवा बागवानी अथवा सहकारी विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें ब्लाक अथवा तहसील अथवा तालुका में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केंद्रों पर अपने आप को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जाए। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(2) ब्लाक अथवा तहसील अथवा तालुका में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण लाभांवित द्वारा नामांकन न करवा पाने के मामले में, राज्य में कृषि अथवा बागवानी अथवा सहकारिता विभागों से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित होता है और आवेदकों अथवा लाभान्वितों से उनके वेब पोर्टल पर अन्य व्यौरो जैसे राशन कार्ड नम्बर, पता, मोबाइल नम्बर के साथ उनके नाम देकर नामांकन के लिए अनुरोध को पंजीकृत कराने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के अलावा सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. 18015/01/2015-ऋ-II (पार्ट)]

डॉ. आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव (कृषि एवं सहकारिता)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2017

S.O. 369(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and Restructured Weather based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) provides a comprehensive insurance cover against failure of the crop thus helping in stabilising the income of the farmers and the farmers shall pay the maximum premium of 2% for all Kharif Food grain and Oilseeds crops, 1.5% for Rabi Food grain and Oilseeds crops and 5% for Annual Commercial or Horticultural Crops;

And whereas, the difference between actual premium and the rate of insurance charges payable by farmers shall be shared equally by the Central and State Governments. The Central Governments' share involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare hereby notifies the following, namely:—

- (1) Farmers availing crop insurance under any of the crop insurance schemes of Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare are hereby required to undergo Aadhaar authentication or furnish proof of possession of Aadhaar.
- (2) Any farmer availing crop insurance under any of the crop insurance schemes of Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare who is not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment and in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of Said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in to get enrolled for Aadhaar).

- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Agriculture or Horticulture or Cooperation Department of the respective State Governments are required to arrange or offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar enrolment centers located within Block or Tehsil or Taluka, the Agriculture or Horticulture or Cooperation Department of the State Governments concerned may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, crop insurance under any of the crop insurance schemes of Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare may be availed by the farmers subject to the production of the following documents, namely:—

- i. Bank passbook with photo; and
- ii. Aadhaar enrolment ID slip, if he has enrolled; or
- iii. his voter ID card; or
- iv. Kisan Photo Passbook; or
- v. NREGA Job card; or
- vi. Driving license along with copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and
- vii. undertaking in the attached format that he is not availing crop insurance for the same crop in the same survey number under some other bank account:

Provided further that the above documents shall be checked by officers specifically designated by the State Government for that purpose.

2. In order to increase the number of farmers availing crop insurance, the Agriculture or Horticulture or Cooperation Departments through their field offices, Krishi vigyan Kendras, Krishi Mitra, all the branches of Commercial Banks, all the branches of Cooperative Societies, all the branches of Regional Rural Banks and any other offices associated with them shall make all the required arrangements including the following, namely:—

- (1) Wide publicity through media and individual notices through all the branches of commercial Banks, all the branches of Cooperative Societies, all the branches of Regional Rural Banks, all the field offices of the Agriculture or Horticulture or Cooperation Department shall be given to applicants or farmers to make them aware of the requirement of Aadhaar to avail crop insurance and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available within Block or Tehsil or Taluka. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.
- (2) In case, the beneficiaries are not able to enrol due to non availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Agriculture or Horticulture or Cooperation Departments in the States are required to create enrolment facilities at convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, ration card number, address, mobile number on their web portal and such requests can also be registered at the field offices.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 18015/01/2015-Credit-II (Pt.)]

Dr. ASHISH KUMAR BHUTANI, Jt. Secy. (Credit & Cooperation)